Request for immediate sanction of international leather complex in Andhra Pradesh

SHRI K. RAMA MOHANA RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, India has exported more than Rs.9000 crores worth of leather and leather-related manufactured goods in 2001-02 to other countries of the world. This clearly shows that there is an immense potential of not only earning foreign exchange but also employment opportunities through the leather exports. Taking cue from this and looking at the advantages that the State of Andhra Pradesh has, the Government of Andhra Pradesh has prepared a master plan to develop a number of leather industrial parks to attract Foreign Direct Investment from tanneries abroad. To achieve this objective, the Government of Andhra Pradesh requested the Government of India for setting up of an international leather complex at Krishnapatnam in Muttkur Mandal of Nellore District of Andhra Pradesh. The Government of Andhra Pradesh has also earmarked 1,000 acres of land for this purpose. On the request made by the Government of Andhra Pradesh, the Government of India approved the proposal in principle. The chief Minister of Andhra Pradesh had also written a letter to this effect on 17* April, 2003, as to give a fillip to the leather industry in Andhra Pradesh. The hon. Minister of Information, Government of Andhra Pradesh, had also urged the Minister of Commerce and Industry in the third week of May 2003, and requested him to immediately accord formal sanction for the international leather complex.

Hence, I request, through you, Sir, the hon. Minister of Commerce and Industry to immediately sanction the proposal for setting up of a international leather complex in Andhra Pradesh. Thank you.

Problems of weavers in Uttar Pradesh

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बुनकरों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में आजमगढ, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, मुबारकपुर, जलालपुर मे बुनकरों की बहुत बडी आबादी है । ये बुनकर कई प्रकार का कपड़ा और गलीचे बनाते हैं जो कि विदेश मे जाता है । इसके बावजूद आज यहां के बनुकर बहुत सी दयनीय हालत मे हैं । इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। प्रथम तो इनके बनाए हुए समान का अब कोई खरीददार नहीं है । पहले सरकार इनके द्वारा निर्मित कपडे और अन्य चीजें लिया करती थी पर अब यह बंद हो गया है । इनको मार्केट में अपना सामान बेचने में बहुत मुश्किले आती है । इसके लिए एक विशेष मार्केट की व्यवस्था की जरूरत है । इनकी एक

बहुत बड़ी समस्या बिजली की कमी है। इन्हें बहुत ही कम बिजली मिलती है और मिलती भी है तो अनियमित रूप में जिससे और कई गडबडियां पैदा हो जाती है । इन सब कारणों से वे बुनकर अपना धरना, प्रदर्शन करते रहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : आप स्पीच नही दे सकते हैं। आप रिटन टैक्स्ट पढियें ।

श्री दारा सिंह चौहान : उपसभाध्यक्ष महोदय । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी एक सांसदों की समिति बनाकर जांच की जाए या न्यायिक जांच कराई जाए, वरना इसके परिणाम बडे गंभीर हो सकते हैं ।

मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विषय में हस्तक्षेप करे तथा बुनकरों के लिए एक विशेष सहायता पैकेज की घोषणा करे ।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इससे अपने आपको संबद्ध करता हूं ।

श्री मुनब्बर हसन (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इससे अपने आपको संबद्ध करता हूं ।

Repatriation of Indian prisoners lodged in Pakistani jails

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) **:** धन्यवाद महोदय, भारत सरकार और संसार के देश इस बात से अवगत हैं कि सन 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान किसी न किसी स्तर पर बंदी बना गए 54 भारतीय योद्धा आज भी पाकिस्तान की जेलों में बदं है और वहां की जेल यातनांए भुगत रहे हैं। देश जानना चाहता है कि पाकिस्तान से समय समय पर कूटनीतिक चर्चा एंव शांतिवार्ता करने वाली केन्द्र सरकार ने इस 54द बदियों के लिए क्या कभी कोई मुद्दा इनकी वापसी या रिहाई को बनाया? पिछले तीस बत्तीस वर्षो में केन्द्र एक दिन भी बिना सरकार के नहीं रहा । क्या आज की कूटनीतिक वार्ता में हमारी सरकार इन बंदियों की रिहाई को अपने ऐजेडे में रखती है? इन रणजुझारे सेनानियों के परिजन यहां उनकी प्रतीक्षा कर रहें हैं, और वे वहां भारत सरकार की कूटनीतिक पहल और उसकी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या हमारे सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडलों और शिष्टमंडलों ने इस दिशा में कोई प्रयत्न किया? आज उनके कुशलक्षेम के क्या समाचार हैं? यह एक गंभीर और सेना तथा समरभूमि की अस्मिता से जुडा हुआ प्रश्न है। भारत सरकार को देश को सारी स्थिति से अवगत रखना चाहिए । इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम कार्यवाही करनी चाहिए । अपनी जवानी का सोना समरभूमि मे स्वाहा करने वाले योद्धाओं को सम्मान अपनी मातृभूमि में वापिस लाने की मांग भारत माता की मांग है। धन्यवाद ।

Request for allocation of funds under Prime Minister's Gram Sadak Yojna Phase-IV to Andhra Pradesh

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, my Special Mention is pertaining to Allocation of funds under Prime Minister Gram Sadak Yojna Phase-IV.